

Newspaper Clips

August 15, 2011

Times of India ND 15/08/2011 P18

Education quota likely to breach 50% ceiling

Kapil Agrees To CPM-BSP's Demand To Amend Law

Akshaya Mukul | TNN

New Delhi: At the insistence of MPs of CPM and BSP, HRD minister Kapil Sibal has agreed to move an official amendment



Kapil Sibal

to the Central Educational Institutions (reservation in admission) amendment bill. A specific provision in the bill stating that reservation in admission, other than the North East, would not be more than 50% is likely to be dropped.

Since there are variations in reservation in admission in central educational institutions — for instance in Nation-

al Institutes of Technology there is a state quota, in Ambedkar University in UP there is no reservation for OBCs and in north-eastern states like Tripura there is more than 60% reservation — MPs felt there was no need to put the provision that reservation, other than N-E states, would not be more than 50%. Though the ministry argued that the provision would not change the ground situation, MPs protested and CPM MPs even said they would move an amendment. It was argued that why put a provision that is already known.

Sources said there are three parts of reservation in the bill. One, in respect of state seats in central educational institutions like NITs, state policy of reservation would be followed.

But in non-state seats of NITs, reservation would be less than 50%. The bill also points out that in some central institutions like Ambedkar University, 49.5% reservation is given to SCs/STs and not to other backward classes.

In north-east states, reservation follows a different pattern since there are no OBCs in most of these states. Tripura and other N-E states have more reservation for STs and in some states, state and central quota put together crosses 50%.

Sources said the bill protects north-east states and says 50% bar for reservation is limited to rest of the country. The bill also seeks to extend the period of implementation of 27% OBC reservation from three years to six years.

Publication: The Times Of India Delhi; Date: Aug 15, 2011; Section: Times City; Page: 9;

'Lack of skill-based, quality education plaguing country'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: India might have supplied skilled workforce globally, but lack of skill-based and quality education is one of the major problems plaguing the Indian education system today, said experts at the Education Times Eduvision on Friday.

At least 25% of the engineers graduating every year remain unemployable, pointed out many experts present at the seminar, which was organized by the Institute of Management Technology to mark the 13th anniversary of Education Times.

Dr Nalin Jena, senior education specialist at the World Bank, shared figures that showed India's economic growth has been "job-poor". According to the data, from 1983 to 2004, the GDP growth rate averaged 6% per year.

"But the job growth was only 2%, that too mostly in the service and unorganized sectors and in micro, small and medium enterprises," said Jena. Dr Arun Mohan Sherry, director & chairman of the joint admission committee at the IMT-Centre for Distance Learning, echoed Jena's views. "India ranks third in the output of graduates after the US and China but in terms of quality, we still lag behind." The seminar brought together experts from across the education sector, who deliberated on diversifying the learning needs for the next generation and providing them



EXPERTS' MEET

with skills to make them industry-ready. Skill-based and quality education is also essential to improve the gross enrolment ratio (GER) of the youth, most of them pointed out. "Unless formal education is linked with skill development, the relevance of the subject will not be understood. There is an urgent need to focus on skill development in higher education," said Rajshekharan Pillai, vice-chancellor of Ignou.

There was enthusiastic participation from students present at the seminar. The experts also dwelt on the extent of use of technology in modern-day education. Abha Sahgal, principal of Sanskriti School, stressed that technology is an enabler, but it cannot replace a real classroom. Some other speakers at the seminar were Manish Sabharwal, member of the Prime Minister's Council on Skills Development; Dr Dilip K Bandyopadhyay, vice-chancellor of Guru Gobind Singh Indraprastha University; and M Sajid, registrar, Jamia Millia Islamia.

Economic Times ND 15/08/2011 P-4

फ्रेशर को बढ़ रहा है नौकरियों का न्योता

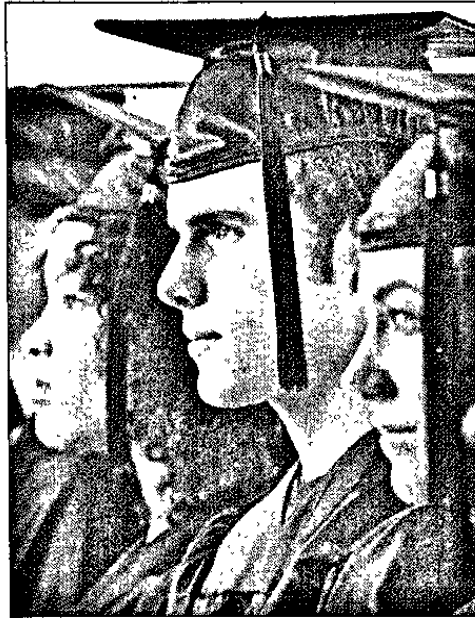
फ्रेश टैलेंट आकर्षित करने के लिए कंपनियां हर साल 5-7% तक बढ़ाती हैं सैलरी पैकेज

महिमा पुरी
नई दिल्ली

दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के अंडरग्रेजुएट आदित्य माथुर को 2010 में डोएचे बैंक से सालाना 32 लाख रुपए की नौकरी का ऑफर मिला था। उन्हें पहले लंदन में बैंक के ग्रेजुएट एनालिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना था फिर उनको दुनिया के किसी देश में पोस्टिंग होती। बैंक ने इस साल एसआरसीसी के ही 20 साल के श्रेय गुप्ता को 39 लाख रुपए सालाना का पैकेज ऑफर किया है। यह डीयू के किसी ग्रेजुएट को मिले पिछले साल के ऑफर के मुकाबले 21 फीसदी ज्यादा है। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि किसी फ्रेशर के लिए नौकरी शुरू करने के लिए इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता।

कंपनियों को सिर्फ अनुभवी लोगों की ही नहीं, बल्कि हर साल फ्रेशर को भरती करने की भी जरूरत पड़ती है। बहुत सी कंपनियां फ्रेशर को भरती करने और उनको अपने साथ बनाए रखने की हरसंभव कोशिश करती हैं। इसके लिए वे पैकेज बढ़ाती रहती हैं और पहले साल में गारंटीड बोनस भी देती हैं।

खासतौर पर पिछले दो साल से हर साल पैकेज में बढ़ोतरी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि नौकरियों की संख्या बढ़ रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि कंपनियों को अब यह बात समझ में आ गई है कि फ्रेशर के साथ काम करने में ज्यादा आसानी होती है। केपीआईटी कर्मिंस के सह संस्थापक और चीफ पीपल ऑफिसर सचिन टिकेकर के मुताबिक, 'फ्रेशर की भरती करना कारोबार के लिहाज से काफी अच्छा होता है। आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में हर कंपनी को लागत



कम-से-कम रखने की जरूरत है। एक तरीका कुछेक साल के बहुत से प्रोफेशनल्स की जगह फ्रेशर की भरती करना हो सकता है।'

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेशर के पैकेज में हर साल कम-से-कम 5 से 7 फीसदी की बढ़ोतरी करती है। फ्रेश टैलेंट को आकर्षित करने और अपने साथ बनाए रखने के लिए कंपनी दूसरे तरीके भी अपनाती है। कंपनी के सीओओ वाई पी वर्मा बताते हैं कि 2011 में एलजी ज्वाइन करने वाले मैनेजमेंट ट्रेनी को कम से कम 5.5 लाख रुपए की

बेसिक सैलरी मिली है। लेकिन कंपनी उनको पहले एक साल के बोनस की भी गारंटी देती है। फ्रेशर बोनस के तौर पर बेसिक सैलरी का अधिकतम 140 फीसदी तक पा सकते हैं। इस हिसाब से उसका सिर्फ बोनस करीब 8 लाख रुपए तक होता है। वर्मा कहते हैं कि कंपनी ऐसा फ्रेशर को आकर्षित करने के लिए करती है, ताकि फ्रेशर को पहले साल के परफॉर्मिंस की चिंता नहीं करनी पड़े। उनका कहना है, 'इसके अलावा हम उन्हें एलजी के कल्चर में डालना चाहते हैं।'

कंपनी ने टेक्निकल साइड में इस साल 65 मैनेजमेंट ट्रेनी और 50 पोस्ट ग्रेजुएट्स की भरती की है। पिछले साल यह आंकड़ा क्रमशः 50 और 40 था। यह काम सिर्फ एलजी ही नहीं कर रही है। डार्वर ने इस साल 13.5 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर मैनेजमेंट ट्रेनी की भरती की है। उसने 2010 में 11 लाख रुपए और 2009 में 10 लाख रुपए का पैकेज दिया था। कंपनी के ईडी, एचआर ए सुधाकर के मुताबिक, 'मैनेजमेंट ट्रेनी का पहला साल कंपनी और उसके कारोबारी तौर तरीकों के बारे में जानने में जाता है। इस साल बिजनेस स्कूल में ज्यादा कंपनियां गई थीं। उद्योग के मानक और मांग को देखते हुए पैकेज बढ़ाया गया है।'

फिक्स्ड सैलरी के रूप में समूचा पैकेज देने से कभी कंपनी को दिक्कत हुई है, यह पूछे जाने पर वर्मा ने कहा कि फ्रेशर करियर की शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा काम सीखना चाहते हैं। इसलिए कंपनी को खास दिक्कत नहीं हुई। पेप्सिको इंडिया भी फ्रेशर का पैकेज साल दर साल बढ़ाती है। कंपनी ने इस साल टॉप बिजनेस स्कूल से 14.5 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर मैनेजमेंट ट्रेनी लिए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले 1 लाख रुपए ज्यादा है।